जनता को लव जिहाद में फंसाकर सरकार जेब काटने में लगी

नई दिल्ली (म.मो.): क्या आप जानते हैं कि किस तरह से भारत सरकार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है? इंडियन आयल की इंडेन गैस के नाम से घर-घर में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई होती है। ठीक इसी प्रकार भारत गैस और एचपी भी घरेलु गैस सप्लाई करते हैं। मोदी सरकार के गठन के बाद से ही गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। सत्ता में आते ही प्रधानमन्त्री मोदी ने आम जनता से अपील की कि जो लोग अपनी गैस सब्सिडी छोड़ सकते हैं वे छोड़ दें ताकि जरूरतमंद को इसका लाभ दिया जा सके। जाहिर है लोगों ने बड़े पैमाने पर गैस सब्सिडी छोड़ भी दी, पर क्या सच में मोदी सरकार ने जरूरत मंदों के लिए ऐसा करवाया था?

65 वर्षीय शोभा के पास इंडेन गैस के नाम से किसी का फोन आया और फोन पर उन्हें बताया गया कि कंपनी ने सर्वे आयोजित किया है जिसमे घर-घर जाकर कंपनी के लोग यह देखेंगे कि आपकी गैस ठीक काम कर रही है या नहीं, दिल्ली में बीते 45 सालों में ऐसा कभी कोई सर्वे नहीं हुआ था इसलिए शोभा को बात जमी नहीं। शोभा घर पर अकेली थीं और बुजुर्ग हैं तो उन्होंने तस्दीक करने के लिए अपने बेटे को इस बात की सूचना दी। उनके बेटे ने जब उसी फोन नंबर पर फोन करके पता किया कि यह किस प्रकार की जांच है तो यहाँ वहां कि बात करने के बाद फोन वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप्प पर अपने सीनीयर राजेश का नम्बर शोभा के बेटे सचिन को यह कहते हुए दिया कि राजेश इंडियन आयल के जीएम हैं।

राजेश से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे इंडियन आयल के जीएम् नहीं हैं, वह तो दिल्ली मसूदपुर गाँव स्थित इंडेन गैस की सोना गैस एजेंसी के मैनेजर हैं। कंपनी ने सर्वे करना शुरू किया है और इस सर्वे के बदले कंपनी लगभग 240 रुपये उपभोक्ता से वसूलेगी। इसके अलावा यदि रेगुलेटर या गैस पाइप खराब है तो कंपनी उसे बदलने के अलग से चार्ज लेगी। राजेश की बताई बात की पुष्टि करने के लिए जब

इंडियन आयल के उपभोक्ता केंद्र के दिए नंबर पर बात की गई तो वहां भी यही सूचना दी गई पर अंदाज अलग था। फोन पर एग्जीक्यूटिव से जब सचिन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि न तो हमने आपको सर्वे के लिए न्योता दिया है और न हमारी गैस में कोई दिक्कत है तो आपको हम किस बात के पैसे दें? यदि आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो कंपनी खुद उसका खर्च वहन करे। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ने सचिन को लगभग धमकाते हुए कहा कि आपसे कोई अलग से नहीं लिया जा रहा पैसा, सारे देश में हो रहा है सर्वे यदि आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिये आपका गैस कन्नेक्शन काट देंगे।

सरकार की इस गुंडागर्दी की लूट में छिपा है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। दरअसल जब भी आप कोई गैस सिलेंडर लेते हैं तो उस पर दिए गए पैसे में कुछ राशि बतौर सुरक्षा बीमा कंपनी के पास जाता है। अब यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, लीकेज या रेगुलेटर से सम्बंधित कारणों से होती है तो कंपनी को बीमे की रकम पीड़ित को देनी पड़ती है। हलांकि ऐसे कितने मामलों में कम्पनी ने बीमा कि रकम चुकता की इसपर शोध होना चाहिए। कोई दुर्घटना न घटे इसके लिए कंपनी की जिम्मेवारी है कि वह अपने सिलेंडर, पाईप, और रेगुलेटर को दुरुस्त रखे। इसपर होने वाले खर्च में मैनपावर का खर्च भी शामिल है सो सरकार ने बड़ी चालाकी से इसे सर्वे के नाम पर पूरे देश की जनता से 240 रुपये वसूलने का जरिया बना लिया। यदि किसी की गैस पाइप या रेगुलेटर में कोई समस्या है तो इसे घर पर सिलेंडर पहुँचाने वाला व्यक्ति ही जिसके पास इसकी ट्रेनिंग होती है ठीक कर देता था।

यदि सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है तो इन उपकरणों को दुरुस्त करने के लिए लगने वाली राशी ले ले। परन्तु आपकी पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर सब ठीक है तो आपसे सिर्फ सर्वे के नाम पर 240 रुपये वसूल लेना साफ गुंडागर्दी है। सरकार ये गुंडागर्दी कर सकती है क्योंकि वह जानती है कि नेटफिलिक्स की सीरीज में मंदिर में चुम्बन वाले सीन पर लव जिहाद फैलने का डर देश के दिमाग में कंक्रीट से भी अधिक मजबूती से बैठ गया है।

मोदी की योजना में निजी कम्पनियों का फायदा ही फायदा

नई दिल्ली चुनावों में कच्ची कालोनी को पक्का करने का शोर ऐसा मचा कि नेता से अभिनेता सब इसका श्रेय लेने को दौड़ पड़े। केजरीवाल को मिलते श्रेय को मोदी के लग्गे-भग्गों ने गली-गली पोस्टर लगाकर छीनने का असफल प्रयास किया। धूम धाम से किये इस प्रचार पर उस वक्त किसी को भरोसा नहीं था और आज की तारीख में केंद्र सरकार ने भरोसा न होने के कारणों पर मोहर लगाने का काम शुरू कर दिया है।

पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की कच्ची कालोनियों को पक्का करने का काम डीडीए के तहत होना तय हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के गाँव में इसके सुगबुगाहट शुरू हुई और जब योजना जमीन पर आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि सरकार किस चालाकी से उनकी जेब काट रही है। डीडीए ने कच्ची कालोनी की जमीनों की पैमाइश कराने का ठेका निजी एजेंसियों को सौंप दिया जिसके तहत ये निजी कम्पनियाँ प्रति वर्गफीट के हिसाब से तय राशी जमीन के मालिक से लेंगी। इस कार्यक्रम को भी जमीन का सर्वे करने के नाम से शुरू कर मकान मालिकों को बताया जा रहा है कि आपकी जमीन की पैमाइश होगी और पैमाइश के बाद ही आगे का कार्यक्रम तय होगा। इस पैमाइश के लिए पैसा मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। 100 गज के प्लाट पर लगभग 1180 रुपये की रकम वसूलने के बाद डीडीए की रसीद की जगह निजी कंपनी की ही रसीद मिल रही है।

जो लोग दिल्ली में कई दशकों से रह रहे हैं उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एक सरकारी महकमा किस तरह किसी निजी कंपनी को नकद लेने और अपनी रसीद देने की सुविधा दे सकता है।

सीबीआई से सेवानिवृत हुए घनश्याम सिंह रावत का मानना है कि जब कालोनी के पक्का होने का अभी कोई पुख्ता सन्देश ही हमे नहीं मिला है तो ये सर्वे और इसके नाम पर ली जाने वाली रकम का क्या उद्देश्य है। हो सकता है भविष्य में कालोनी पक्की हो जाये तो क्या इस रकम को सरकार रजिस्ट्री या अन्य किस्म की फीस में एडजस्ट करेगी। और इससे भी बड़ी संभावना है कि कालोनी पक्की ही न हो तो क्या सर्वे के नाम पर दी गई ये रकम हमे वापस मिलेगी, अगर हाँ तो किस रूप में?

इसी प्रकार के ढेरों सवाल लिए कई लोग डीडीए की वेबसाईट पर दिए नम्बरों पर फोन कर पूछ रहे हैं कि जब जमीन को पक्का कर उसपर रजिस्ट्री और भूकर डीडीए ही वसूलेगा तो उसके सर्वे का खर्च आम जनता की जेब से वसूल कर निजी कंपनियों के हवाले करने का क्या अर्थ है?

सवाल कई हैं पर जवाब में सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि जब भारत सरकार ने यही नियम तय कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा तो देना पड़ेगा। यानी मोदी जी कालोनी पक्की करें या न करें पर इसमें निजी कंपनियों को मुनाफा पक्का करवाया जाएगा।

आपका-हमारा सरोकार

कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस क्यों

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने का विरोध किया है। दोनों ने आरबीआई की इंटरनल वर्किंग कमिटी द्वारा देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश को विनाशकारी करार दिया है।

Linkdin में लिखे साझा ब्लॉग में रघुराम राजन और विरल आचार्य ने कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश पर हैरानी जताई है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने से देश की आर्थिक और राजनीतिक ताकत कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों में पहुंच जाएगी। इस सिफारिश का बड़ा फायदा कर्ज में डूबे कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक दलों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले कॉरपोरेट को होगा।

राजन और आचार्य ने पेमेंट बैंक के लिए बैंकिग लाइसेंस हासिल करने के लिए जरूरी बतौर पेमेंट बैंक ऑपरेशन के सर्विस की सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल करने की सिफारिश पर भी हैरानी जताई है।

आप को बता दें कि शुक्रवार को ही निजी क्षेत्र के बैंकों में मालिकाना हक के गाइडलाइंस और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को लेकर आरबीआई के इंटर्नल वर्किंग ग्रुप ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट को आरबीआई ने सार्वजनिक किया था। इस कमेटी ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन कर बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की है।

आरबीआई के इंटर्नल वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में बैंक के प्रोमोटर की हिस्सेदारी को मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी करने और वैसे गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) जिनकी पूंजी 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है और 10 साल कारोबार में पूरा हो चुका है उनको भी बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की है।

कहा जा रहा है कि देश के दो बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पेमेंट बैंक आपरेशन के धंधे में उतरने वाले हैं। उनके लिए सारी तैयारी की जा रही है। ऐसी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर इन दोनों की नजर है। उन्हें खरीदकर किसी भी समय ये लोग अपना धंधा शुरू कर सकते हैं।

टिकट नहीं कट रही है बाबू, जेब कट रही है!

मोदी जी जहाँ बैठे हैं यानी कि दिल्ली और मोदी जी जहाँ से चुन के आये हैं, मतलब बनारस, यहाँ आने जाने के लिए चलने वाली कई रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी फेयर लगाया जा रहा है। कोरोना काल के नाम पर इज्जत बचाने में जुटी भाजपा सरकार की मारक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीँ सरकार ने तय कर लिया है कि जब तक आम नागरिक के खून पसीने की कमाई की एक-एक पाई छीन नहीं लेगी चैन से न बैठेगी न बैठने देगी।

61 साल के राधेश्याम फरीदाबाद में रिक्शा चलाते हैं। सेक्टर 3 से सेक्टर 9 के आस-पास की हार्डवेयर दुकानों से माल उठाना और उनको घरों तक पहुंचा कर महीने में । हजार कमा लेते हैं। बनारस के रहने वाले राधेश्याम लॉकडाउन में घर नहीं जा सके तो लोगों से मांग-मांग कर काम चलाया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, रिक्शा चलने लगा पर कमाई पहले जैसे नहीं रही। अब कुछ कम कमाते हैं पर ये हैं कि छिटपुट काम मिल जाता है। इस बार त्यौहार पर गाँव जाने का सोचा तो लगा अब कभी गाँव जा ही नहीं सकेंगे। एक आदमी का ट्रेन का भाड़ा लगभग 1500 रूपया था और चालू डब्बा तो रहा ही नहीं जो बैठ लें। इसलिए अब यहीं रह गए कि छोड़ो दिवाली और छठ।

राधेश्याम की ही तरह राहुल ने अपनी माता की बनारस जाने के लिए ट्रेन में टिकट बुक करवाई। कोरोना के भय से एसी टू का टिकट लिया जो उन्हें लगभग 2100 रुपये का पड़ा। इतना महंगा टिकट लेकर पहली बार सफर करने जा रहीं

उनकी माता की तबीयत कुछ ठीक न होने के कारण मात्र 4 घंटे बाद ही टिकट को कैंसिल करवाया तो पाया कि 600 रुपये काट लिए गए और बाकी के पैसे तीन दिन बाद खाते में आने का एक सन्देश भेज दिया गया आईआरसीटीसी द्वारा।

प्रधानमंत्री ने रेलवे को बिकने न देने का जुमला देकर पहली निजी ट्रेन तेजस को हरी झंडी दी थी। मीडिया ने महीनो शोर मचाये रखा कि कितनी रफ्तार से ट्रेन बनारस पहुच गई। कुछ दिन पहले वही ट्रेन अब बंद कर दी गई, आज मीडिया में कोई शोर नहीं कि क्यों बंद हुई, क्या कारण थे जो ट्रेन बंद हुई? तो कारण राधेशयाम और राहुल की समस्याओं से कुछ अलग नहीं। यदि जल्दी ही इनका निवारण आम आदमी के हक में नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि तेजस के साथ-साथ सभी रेलें बंद हो जाएँ।